माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मकता: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

संजीव शुक्ला*

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार व प्रचार के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किये गए प्रयासों की वजह से हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है। माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो उच्च शिक्षा की आधार शिला तैयार करती है। परंतु वर्तमान समय में शिक्षा की यह कड़ी कमजोर एवं उपेक्षित रही है। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या करते हुए यह लेख इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन की सिफ़ारिश करता है। इसी संदर्भ में लेख में माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं इसके सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है।

"स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे छात्र प्रगतिशील प्रजातांत्रिक-सामाजिक प्रणाली में सृजनात्मक रूप से भाग लेने में समर्थ हो सके।"

मुदालियर आयोग (1952)

शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा ही वह सशक्त उपागम है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न संस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा का समन्वित विकास कर समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बनता है। नागरिकों को अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित

**प्रवक्ता* (बी.एड.विभाग) श्री गाँधी महाविद्यालय, सिंधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

करना गुणात्मक शिक्षा का कार्य है। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण से दूर होकर सैद्धांतिक व सूचनात्मक होती जा रही है। समाज एवं उसकी समस्याओं से शिक्षा का संबंध-विच्छेद सा हो गया है। शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव-सा है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे कई स्तर बन गए हैं, जहाँ माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण उदासीन है, वहीं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की आधारशिला तथा तैयारी की अवस्था है। यदि इसकी नींव ही कमज़ोर हो तो फिर उच्च शिक्षा का भवन कैसा बनेगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की कड़ी में सबसे कमज़ोर, उपेक्षित एवं दोयम दर्जे की भूमिका का निर्वाह कर रही है । अत: आवश्यकता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन कर इसे सशक्त एवं जनोपयोगी बनाया जाये, जिससे इस अवस्था में प्रवेश करने वाले किशोर छात्र-छात्रा शिक्षणोपरांत सुयोग्य नागरिक बनकर जीवन में प्रवेश करके समाज एवं राष्ट्र की उन्नति कर सकें।

उद्देश्य

शिक्षा आयोग (1964-66) ने शिक्षा को जीवन से संबंधित आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया, जिससे यह राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन सके। शिक्षा आयोग ने पाँच-सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया, जो निम्नवत् है -

1. शिक्षा को उत्पादकता के साथ संबंधित करना।
2. शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करना।
3. शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।
4. उत्सुकता को जगाना, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित करना तथा अनिवार्य कौशलों के विकास द्वारा समाज का आधुनिकीकरण करना।
5. सामाजिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना इत्यादि प्रमुख हैं।

चुनौतियाँ

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में अधोलिखित चुनौतियाँ प्रमुख हैं-

1. माध्यमिक शिक्षा में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात मात्र 43.82% है जबकि प्राथमिक शिक्षा में सफल अनुपात नामांकन 93.32% है, अर्थात लगभग 56% छात्र माध्यमिक शिक्षा से आज भी वंचित हैं। (*सातवां अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली-2002)
2. कोठारी आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि शिक्षा पर आवंटन का 2/3 विद्यालयी शिक्षा पर, एवं 1/3 उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। परंतु आज शिक्षा पर आवंटित बजट प्रावधान के अंतर्गत सर्वाधिक (50 प्रतिशत) प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है।

3. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने माध्यमिक शिक्षा की अधोलिखित तात्कालिक कमियों का उल्लेख किया था —
   क. माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुरूप नहीं है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है ।
   ख. शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम के प्रारूप के कारण छात्रों में सहयोग की भावना, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास समुचित नहीं हो पाता है।
   ग. माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली वैध एवं विश्वसनीय नहीं है, अतः छात्रों की योग्यताओं, सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा का समुचित मूल्याँकन नहीं हो पाता है।
   घ. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय-ज्ञान केंद्रित है। इसमें जीवन-संबंधी कार्यप्रणाली तथा समस्याओं का बोध नहीं कराया जाता है।
   ङ. माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक-छात्र संबंध एवं अन्तःक्रिया का अभाव होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
   च. कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावी शिक्षण हेतु अव्यावहारिक होता है।
   छ. शिक्षणवृत्ति आकर्षक नहीं है।
4. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण प्रणाली मुख्यतया ''चाक एवं टाक'' विधि तक ही सीमित है। अध्यापन कार्य परंपरागत रूप में केवल व्याख्यान विधि पर ही आधारित होती है।
5. परीक्षा-केंद्रित माध्यमिक शिक्षा के कारण अनुचित साधनों का प्रयोग एक जीवन-पद्धति बन गया है, जो शिक्षकों को चयनात्मक अध्यापन एवं छात्रों को चयनात्मक अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करती है। सूचना एवं उपाधि को ही शिक्षा का मूल उद्देश्य का पर्याय समझा जाने लगा है।
6. परीक्षा-केंद्रित एवं सूचना-केंद्रित होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा का पूर्णतः अभाव है।
7. शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन का होना। वर्तमान सूचना-संचार युग में शिक्षा को एक 'वस्तु' माना जा रहा है, परिणामतः नैतिक मूल्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का स्थान धनार्जन ने ले लिया है जिससे पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का अवमूल्यन हुआ है।
8. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन सिर्फ छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित है, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष पूर्णतः उपेक्षित हैं, जिससे छात्रों की निर्णय शक्ति, तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति, एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन का अभाव दिखता है।
9. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया केवल स्मृति स्तर के शिक्षण तक ही सीमित है, जो छात्रों को रटने पर बल देती है, तथा अवबोध, परावर्तन,

संश्लेषण एवं विश्लेषण का पूर्णत: अभाव दिखता है।

10. शिक्षक एवं छात्रों के अध्ययन-अध्यापन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के कारण शिक्षण संस्थाएँ सिर्फ छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा की शरणस्थली बन कर रह गई हैं।

संभावनाएँ

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रतिबद्धता, सकारात्मक सोच एवं मिशनरी प्रयास द्वारा सार्वभौमिकरण की संस्कृति विकसित कर, चुनौतियों के संदर्भ में अधोलिखित रूप में समाधान के प्रयास किये जा सकते हैं—

1. माध्यमिक शिक्षा को सिर्फ सूचनात्मक, सैद्धांतिक एवं संज्ञानात्मक न बनाकर इसे भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के समन्वित विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
2. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को स्मृति स्तर (रटने पर ज़ोर) के शिक्षण से अवबोध एवं चिंतन स्तर के शिक्षण की तरफ उन्मुख किया जाये।
3. माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति को ''चाक एवं टाक'' से सूचना एवं संचार तकनीक की तरफ प्रतिमान परिवर्तित किया जाए। विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान किये जायें।
4. माध्यमिक शिक्षा से ट्यूशन एवं कोचिंग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर शिक्षक-छात्रों में कक्षा शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य संस्कृति विकसित की जाए।
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में अधोलिखित संस्तुतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये —
   क) माँग के अनुरूप परीक्षा का आयोजन।
   ख) पास-फेल लिखने की जगह पुन:परीक्षा वांछनीय।
   ग) विद्यालय में सहायता एवं परामर्श केंद्र उपलब्ध कराना।
   घ) पाठ आधारित परीक्षा की जगह समस्या समाधान एवं क्षमता आधारित मूल्यांकन।
   ङ) सूचना को ज्ञान समझने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण।
   च) विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक और भावी कार्य-कौशलों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना।
   छ) शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता में सुधार से संबंधित तथ्य सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों में समाहित हो।
   ज) माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा पारंपरिक विषयों की जगह नये विकल्पों (व्यावसायिक विकल्प) को चुनने की छूट दी जाये।
6. माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करके 25-40% प्रश्न लघुत्तरीय एवं बहुविकल्पीय को समाहित कर छात्रों के तनाव को कम कर उनके उपलब्धि (अंकन) में वृद्धि किया जा सके।
7. शिक्षकों के दायित्व-बोध के निर्धारण हेतु मानकों का निर्धारण किया जाये।

8. माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति एवं शिक्षण गतिविधियों में अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

निष्कर्षत: वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा संक्रमण काल से गुज़र रही है। आज सूचना को ज्ञान का पर्याय एवं शिक्षा को साधन के साथ-साथ साध्य बना दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित रहकर, केवल प्रमाणन तक रह गया है। शिक्षण संस्थाओं से शैक्षणिक परिवेश प्राय: लुप्त हो गये हैं, न ही कक्षा में ज्ञान-पिपासु छात्र दिखते हैं, न ही उनको ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक। कोठारी आयोग का वक्तव्य–'भारत का भाग्य कक्षाओं में आकार ले रहा है' –एक कोरी कल्पना मात्र रह गई है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये शिक्षण संस्थाओं में संख्यात्मक वृद्धि तो हुई, परंतु शिक्षा की गुणात्मकता में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण समाज में मूल्यों का अवमूल्यन, सरकारी नीतियाँ एवं उनके क्रियान्वयन में सरकारी तंत्र की उदासीनता है।

वर्तमान में केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं वैश्विक पहुँच के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक सर्वव्यापी योजना प्रारंभ की है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का मुख्य उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 8 से 10 तक) का विस्तार करना तथा उसका स्तर सुधारना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(RMSA), माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (USE) का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार की नवीनतम पहल है।

लाखों बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित सर्वशिक्षा अभियान काफी हद तक सफल रहा है एवं इसने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचे को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार— "सर्व शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागू होने से बड़ी संख्या में छात्र उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए ज़बरदस्त मांग उत्पन्न कर रहे हैं।"

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस संबंध में मार्गदर्शक तत्व हैं– कहीं से भी पहुंच, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासंगिकता, विकास, पाठ्यक्रम एवं ढाँचागत पहलू। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभियान बराबरी की ओर बढ़ने का मौका देता है। इस अभियान में आम स्कूल की परिकल्पना प्रोत्साहित की जाएगी। यदि प्रणाली में ये मूल्य स्थापित किये जाते हैं, तो अनुदानरहित निजी विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालय समाज के निचले वर्ग के बच्चों एवं गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के बच्चों को उचित अवसर देना सुनिश्चित

कर माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (USE)के लिए उचित योगदान देंगे। इस अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास एवं सैद्धांतिक अवधारणा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके उद्देश्य प्राप्त करने हेतु शिक्षा जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों, नीति-नियामकों, समाज-सेवियों, प्रशासकों एवं शिक्षकों को जन आंदोलन चलाकर इस मिशन के प्रति सकारात्मक सोच एवं प्रतिबद्धता विकसित करनी होगी, जिससे सही अर्थों में माध्यमिक शिक्षा जीवन की प्रयोगशाला बन कर गुणात्मक उच्च शिक्षा के लिए मज़बूत आधार प्रदान कर सके।

संदर्भ

राजपूत, जगमोहन सिंह, 2009, *शिक्षा में कौशल की अनदेखी* (दैनिक जागरण, लखनऊ, पृष्ठ-6)।

सिंह, कर्ण, 2009, *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास,* लखीमपुर खीरी, गोविन्द प्रकाशन।

पाठक, पी.डी., 2005, *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

त्यागी, गुरूशरण दास, 2002, *भारत में शिक्षा का विकास,* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

लाल, रमन बिहारी, 2010, *भारतीय शिक्षा का इतिहास: विकास एवं समस्याएँ,* आर.लाल बुक डिपो, मेरठ।

www.indg.in Rashtriya Madhyamik shiksha Abhiyan

एन.सी.ई.आर.टी. 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नयी दिल्ली।